

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 603वीं बैठक दिनांक 04/11/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9356/2022 Shri Dinesh Gupta, F-88/35, Tulsi Nagar, Dist. Bhopal, MP - 462003, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.10 ha. (40000 Cum per annum) (Khasra No. 148), Village - Rampurghosi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 148), Village - Rampurghosi, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 2.10 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1762 दिनांक 17/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण भाग से होते हुए एक कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा दक्षिण दिशा में 75 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला एवं 250 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। समिति ने पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपठनीय है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ पठनीय जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिण भाग से होते हुए एक कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा दक्षिण दिशा में 75 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला एवं 250 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आंवटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. चूँकि आंवटित स्थल पहाड़ पर स्थित है, अतः खनिज परिवहन मार्ग तथा सरफेस रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ पठनीय डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें ।

2. **Case No 9366/2022 M/s Shri Gordhan Gopal Enterprises LLP, Partner, Shri Himanshu Veerwani, 61, Scheme No. 101. Manik Bagh Road, Dist. Indore Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (19950 Cum per annum) (Khasra No. 3/2), Village - Sawaliyarundi, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/2), Village - Sawaliyarundi, Tehsil - Ratlam,

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

Dist. Ratlam (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु वीरवानी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1004 दिनांक 25/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तरी दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा दक्षिण दिशा में 450 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। गूगल इमेज अनुसार आवंटित स्थल से सरफेस ड्रेन निकल रहा है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनकी स्थिति मय फोटोग्राफ के तथा संरक्षण योजना प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ नवीन अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तरी दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा दक्षिण दिशा में 450 मीटर पर प्राकृतिक नाला है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. गूगल इमेज अनुसार आवंटित स्थल खुदा हुआ तथा उसमें से सरफेस ड्रेन निकल रहा है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इनकी स्थिति मय फोटोग्राफ के तथा संरक्षण योजना प्रस्तुत की जाये।
3. खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

3. Case No 9362/2022 M/s Krishna Minerals, Shri Jayant Goswami, Partner, 26, Commercial Complex, Housing Board Colony, Dist. Katni, MP - 483501 Prior Environment Clearance for Laterite & Fireclay Deposit Quarry in an area of 6.350 ha. (Laterite - 77618 Tonne per annum, Clay - 25989 Tonne per annum) (Khasra No. 231, 232, 233, 234), Village - Majhgawan, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP)

This is case of Laterite & Fireclay Deposit Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 231, 232, 233, 234), Village - Majhgawan, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 6.350 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री जयंत गोस्वामी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1952 दिनांक 26/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी भाग से होते हुए एक कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर जल रोकने की संरचना, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में लगभग 750 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसमें इसका विवरण दर्ज हो प्रस्तुत की जायेगी । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर,

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्वी भाग से होते हुए एक कच्चा रोड़, दक्षिण दिशा में 90 मीटर पर जल रोकने की संरचना, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में लगभग 750 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे।

4. **Case No 9363/2022 M/s Baerlocher India Additives Pvt. Ltd, Shri Akhilesh Kumawat, India Operation Head, Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP - 455001, Prior Environment Clearance for Expansion of Manufacturing of Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps at Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, , MP**

This is case of Prior Environment Clearance for Expansion of Manufacturing of Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps at Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP For capacity expansion from 65,500 MTPA to 1,38,700 MTPA. In Cat. – 5 (f).

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

The case was presented by Env. Consultant Shri Shubham Dubey from M/s. Envisolve LLP, Indore and PP Shri Abhishek Kumawat on 4/11/22. During presentation PP submitted that previous EC was obtained in the year 2020 and now they are proposing expansion from 65,500 MTPA to 1,38,700 MTPA. The plant is located in the notified industrial area of Dewas.

During presentation it was observed by the committee that entire project site is not uploaded on Parivesh portal (KML file) and the part of site where expansion is proposed is not visible online. PP submitted that by mistake they have uploaded only part of land and apologized for this mistake. Committee after deliberations recommends that since part of land where expansion is proposed is not available online, thus PP should submit complete details of land on a map showing existing plant and area of land allocated for proposed expansion through ADS for further consideration of TOR.

5. Case No 9370/2022 M/s J.K.Cement Ltd, Unit - J.K.White, Unit Head, Shri Ganesh Sahu, Village Rupaund, Tehsil – Badwara, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 9.13 ha. (Dolomite - 110075 Tonne per annum, Sub-grade - 15,725 Tonne per annum) (Khasra No. 74/1, 74/2, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87/1, 87/2, 169/1, 169/2), Village - Bhaganwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP)

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 74/1, 74/2, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87/1, 87/2, 169/1, 169/2), Village - Bhaganwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 9.13 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश साहू, यूनिट हेड (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1951 दिनांक 26/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है। चूंकि प्रश्नाधीन खदान का रकबा 09.13 हे. है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 45 मीटर पर एक पक्का रोड़, दक्षिण-पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ एवं पूर्व दिशा में 225 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 2125 दिनांक 14/09/22 उक्त खदान को जिला सर्वेक्षण सर्वेक्षण रिपोर्ट पृष्ठ क्रमांक-49 में दर्शित सूची के सरल क्रमांक-9 में सम्मिलित किया जाकर उक्त

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक/सिया को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया है । समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदिन नवीन जिला सर्वेक्षण प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:-

1. खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 45 मीटर पर एक पक्का रोड़, दक्षिण-पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ एवं पूर्व दिशा में 225 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान (मय गेमप्रूफ फेंसिंग) निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें ।

6. Case No 7604/2020 M/s Bhagchand Sancheti, Ward No. 7, Nehru Chowk, Waraseoni, Dist. Balaghat, MP - 481331 Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 7.713 ha. (50000 tonne per annum) (Khasra No. 250/1, 250/3, 251), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP)

This is case of Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 250/1, 250/3, 251), Village - Ambejhari, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) 7.713 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

The case was previously scheduled for presentation, in 468th SEAC meeting dated 16/12/2020 but neither the Project Proponent (PP) nor his representative was present to explain the query which might be raised or to make any commitment which may be desired by the committee during the deliberation. Earlier PP was also absent in SEAC meeting 466th SEAC meeting dated 26/11/2020 & 458th SEAC meeting dated 22/09/2020. Committee decided that since sufficient opportunities has been given to the PP for appraisal of their case but PP remains absent thus committee decided that case shall be returned to SEIAA for delisting assuming that PP is not interested to continue with the project.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर दिनांक 10/10/22 के द्वारा प्रकरण को रिलिस्ट करने के अनुरोध पर प्रकरण को सिया द्वारा रिलिस्ट कर परीक्षण हेतु दिनांक 20/10/22 को सेक को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज सेक की 603वीं बैठक दिनांक 04/11/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

7. Case No 9374/2022 M/s M.P.Minerals, Partner, Shri Kaushal Kishore, 205, Niwasi Panchvati, Vinayakpur, K.P. University, Dist. Kanpur, UP - 208024 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.35 ha. (44289 Cum per annum) (Khasra No. 307/3/K), Village - Lilaury, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 307/3/K), Village - Lilaury, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna (MP) 4.35 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री कौशल किशोर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आर.के. चौबे, मेसर्स एटमोस सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रा.लि., नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1340 दिनांक 18/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्वी भाग में 260 मीटर, उत्तर भाग में 130 मीटर तथा पश्चिमी भाग से 350 मीटर की दूरी पर आबादी है तथा दक्षिण भाग में 60 मीटर पर रोड़ है गूगल इमेज के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

कच्चा रोड या पक्का रोड है अतः परियोजना प्रस्तावक इस रोड की वास्तविक स्थिति व रोड एवं आबादी के लिए संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि लीज का दक्षिण-पूर्वी भाग खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको खदान इसी स्थिति में आवंटित हुई है तथा इस भाग पर एक अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत थी, जिसके द्वारा खनन कार्य किया गया था। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 21/06/22 के अनुसार जिला डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2016-17 में बनी है, जिसमें ग्राम लिलौरी शामिल है। उपरोक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में स्वीकृत उत्खनिपट्टा शामिल किया जावेगा। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदिन नवीन जिला सर्वेक्षण प्रस्तुत करें, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्वी भाग में 260 मीटर, उत्तर भाग में 130 मीटर तथा पश्चिमी भाग से 350 मीटर की दूरी पर आबादी है तथा दक्षिण भाग में 60 मीटर पर रोड है गूगल इमेज के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कच्चा रोड या पक्का रोड है अतः परियोजना प्रस्तावक इस रोड की वास्तविक स्थिति व रोड एवं आबादी के लिए संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे।

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

8. **Case No 9352/2022 M/s Basa Buildcon Partner- Shri Abul Vakar S/o Shri Abdul Kalam, R/o- G-9, Jhumera Complex Near Hotel Manal, A.B. Road Vishwas Banjari, Post - Bhatkhedi, Tehsil - Mhow, District Indore (M.P.), Prior Environment Clearance for Expansion Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (from 22022 Cum pr annum to 75000 Cum per annum) (Khasra No. 1022/2), Village - Kheda, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1022/2), Village - Kheda, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अबुल बाकर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 26/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 05.00 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 620 मीटर तथा उत्तर दिशा में 320 की दूरी पर आबादी है तथा दक्षिण दिशा में 390 मीटर पर व्हीकल टेस्टिंग ट्रेक है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के उत्तर दिशा की ओर से खुदी हुई दिख रही है, इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण क्षमता विस्तार 22022 घनमीटर/वर्ष से 75,000 घनमीटर/वर्ष का है तथा पिट पूर्व में की गई खनन का है। प्रकरण में पूर्व में ई.सी. पत्र क्रमांक 48 दिनांक 09/02/17 के माध्यम से डिया द्वारा जारी की गई थी। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जबलपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 18 के सरल क्रमांक-9 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेकजर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी. ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

1. खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 225 मीटर की दूरी पर आबादी, दक्षिण दिशा में 650 मीटर पर नदी, पूर्व दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड तथा पश्चिम दिशा में खदान अंदर से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पालन प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
4. सरफेस रनआफ मैनेजमेंट प्लान (खदान के पहाड़ पर स्थित होने के कारण) ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
10. ओवरल बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

9. Case No 9360/2022 Shri Abul Vakar, Owner, 205, Karodiya Chopati, Tehsil - Mhow, Dist. Indore, MP - 453441, Prior Environment Clearance for Expansion Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (Expansion from 33,756 to 60000 Cum per annum) (Khasra No. 1021/1), Village - Kheda, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1021/1), Village - Kheda, Tehsil - Dhar, Dist. Dhar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अब्दुल बकर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंगेक, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1327 दिनांक 30/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक को लीज दिनांक 15/12/17 को आवंटित हुई है तथा गूगल की पूर्व इमेज देखने से यह स्पष्ट होता है कि

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन क्षेत्र खुदा हुआ है तथा आवंटित खनन क्षेत्र में वर्ष 2018 से खनन कार्य किया गया है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा कोई खनन कार्य नहीं किया गया है किंतु पास की खदानों द्वारा त्रुटिवश उनके आवंटित क्षेत्र में खनन कार्य किया गया है जिस कारण पिट दिख रहा है। समिति ने चर्चा कर यह अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संबंधित खनिज अधिकारी का यह प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा आवंटित क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया गया है प्रस्तुत करेंगे। यदि परियोजना प्रस्तावक संबंधित खनिज अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो प्रकरण बॉयलेशन का माना जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर दिशा में 340 मीटर तथा पूर्व दिशा में 750 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में 360 मीटर पर पक्का रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 500 मीटर पर व्हीकल टेस्टिंग ट्रेक है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक-3.2 के सरल क्रमांक-31 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के उत्तर दिशा में 340 मीटर तथा पूर्व दिशा में 750 मीटर पर आबादी, उत्तर दिशा में 360 मीटर पर पक्का रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 500 मीटर पर व्हीकल टेस्टिंग ट्रेक है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
3. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ वन विभाग से चर्चा कर यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

5. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
6. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
8. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

10. Case No 9368/2022 M/s Maa Narmada Crusher, Shri Ram Lal Mandloi, Prop., Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.90 ha. (8858 Cum per annum) (Khasra No. 46/1Peki), Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 46/1), Village - Sondul, Tehsil - Manawar, Dist. Dhar (MP) 2.90 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रामलाल मंडलोई (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3117 दिनांक 11/11/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 640 मीटर पर उद्योग, उत्तर दिशा में 390 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 570 मीटर पर आबादी है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रश्नाधीन खदान के अंदर पश्चिम दिशा में मकान हैं, अतः इनका वर्तमान उपयोग, वास्तविक स्थिति तथा उत्खनन के दौरान इनकी उपयोगिता के विवरण के साथ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान पूर्वी भाग खुदा हुआ है जहाँ पर गूगल इमेज अनुसार खनन कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा अज्ञानतावश वर्ष 2020-21 में बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के खनन कार्य किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के तालिका क्रमांक-8 के सरल क्रमांक-25 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । समिति ने पाया कि प्रस्तावित खदान का

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

रकबा डीएसआर में 3.000 हे. दर्ज है जबकि प्रस्तावित खदान का रकबा 02.90 हे. है, अतः इस संबंध में खनिज अधिकारी से स्थिति स्पष्ट कराई जाये। पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के खनन कार्य करने बावत् उनके द्वारा यह प्रकरण वॉयलेशन की श्रेणी में आवेदन किया गया है ।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in above notifications and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 and Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. The PP shall stop all the mining operations till the grant of EC.
2. Project description, its importance and the benefits.
3. Protection nplan for nearby industry and human settlement shall be prepared and discussed in the EIA report.
4. Cummulative assessment of all the mines located in the 2.5 kms of the allotted mines shall be carriedout and discussed in the EIA report.
5. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
6. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

7. There is slight difference in the area of sanctioned lease in the DSR and approval letter hence same shall be redrafted with the concerned MO and attached with the EIA report.
8. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
9. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO₂, NO_x & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
10. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
11. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
12. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
13. Management of solid waste and other mine waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and top soil management plan shall be discussed in the EIA report.
14. Soil profile for suggesting plantation species through trial pits shall be studied and discussed in the EIA report.
15. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
16. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
17. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
18. The PP shall also discuss and calculate the penalty prescribed in EIA report for violation cases as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

11. Case No 9375/2022 Shri Deepak Gurjar, Lessee, Village - Sejwani, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore, MP -453001. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (11000 Cum per annum) (Khasra No. 5), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 5), Village - Rawad, Tehsil - Depalpur, Dist. Indore (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक गुर्जर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1838 दिनांक 29/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 360 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पश्चिम दिशा में 235 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 20 के सरल क्रमांक-16 पर दर्ज है। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने इस खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किए गए आवेदन में नई खदान उल्लेखित किया है जबकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान को वर्किंग होने का उल्लेख है तथा आवंटित क्षेत्र भी खुदा हुआ दिख रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित स्थल में खुदाई 2017 में हुई है जबकि उनको आवंटन 2019 में हुआ है। समिति ने चर्चा कर यह अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संबंधित खनिज अधिकारी का यह प्रमाण पत्र कि उनके द्वारा आवंटित क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया गया है प्रस्तुत करेंगे। यदि परियोजना प्रस्तावक संबंधित खनिज अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो प्रकरण बॉयलेशन का माना जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक ने बिना पर्यावरणीय अभिसवीकृति के उत्खनन कार्य किया है तो प्रकरण बॉयलेशन की श्रेणी में प्रस्तुत करेंगे तथा यह टॉर स्वतः निरस्त माना जावेगा। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के पूर्व दिशा में 360 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पश्चिम दिशा में 235 मीटर पर आबादी है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. इस खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु किए गए आवेदन में नई खदान उल्लेखित किया है जबकि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान को वर्किंग होने का उल्लेख है तथा आवंटित क्षेत्र भी

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

खुदा हुआ दिख रहा है, अतः परियोजना प्रस्तावक संबंधित खनिज अधिकारी से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करवाकर ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करेंगे । यदि परियोजना प्रस्तावक ने बिना पर्यावरणीय अभिसवीकृति के उत्खनन कार्य किया है तो प्रकरण वॉयलेशन की श्रेणी में प्रस्तुत करेंगे तथा यह टॉर स्वतः निरस्त माना जावेगा ।

3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें ।

12. Case No 9377/2022 Shri Balram Jat, Lessee, House No. 101-1, Village - Panchad, Dist. Ratlam, MP – 457222. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 273/1), Village - Nogovaakalo, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No.273/1), Village - Nogovaakalo, Tehsil - Ratlam, Dist. Ratlam (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री बलराम जॉट (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1679 दिनांक 16/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि इस प्रकरण के को-आर्डिनेट माइन प्लॉन में गलत अनुमोदित हुए हैं तथा माइन के गलत को-आर्डिनेट ही केएमएल में अपलोड किए गए हैं जिससे आवंटित खनन की सही लोकेशन गूगल पर दर्शित नहीं हो रही है। उनके द्वारा संबंधित खनन अधिकारी से आवंटित स्थल के वास्तविक को-आर्डिनेट प्राप्त करने हेतु पत्र क्रमांक 1933 दिनांक 03/11/22 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, अतः समिति से अनुरोध है कि उनको पुनरीक्षित को-आर्डिनेट प्रस्तुत करने बावत् 15 दिवस का समय दिया जाये। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक संबंधित खनिज अधिकारी से वास्तविक को-आर्डिनेट प्राप्त कर 15 दिवस में ऑनलाईन प्रस्तुत करने बावत् ए.डी.एस. जारी किया जाये।

13. **Case No 9252/2022 M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP. Environment Clearance for Proposed at Proposed “Sage Golden Spring” Residential Apartment located at Khasra No. - (10/1, 12, 13, 14, 15), (10/2/1, 12, 13, 14, 15), 11/1, (16/1, 18, 21), (16/2, 18, 21) 17/1/1, 17/1/2, 17/2/2, 17/3/1, 17/3/2, 28/1/1, 28/1/2, 28/2/1, 28/2/2, 29/1/1, (A) 29/1/1 (B) 29/1/2/1, 29/1/2/2, 84/1/1, (84/2/1, 85, 86/1), 84/2/2, 86/2, Village – Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal (M.P.). Total Plot Area – 47170.00 Sq.mtr. (4.717 ha.), Built Up Area - 98714.54 square meter ha., Cat. - 8(a). Building and Construction projects. Env. Con. -Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan).**

This is case of Environment Clearance for Construction of "M/s Vrindavan Construction is developing “Sage Golden Spring” Residential Apartment Located at Village: Damkheda, Patwari Halka No. 21, Tehsil – Huzur & District – Bhopal, Madhya Pradesh on a land admeasuring 47,170 Square meter (4.717 Ha).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 583rd SEAC dated 30/06/2022 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded by SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

The case was presented in 600th SEAC meeting dated 18-10-22 by Env. Consultant Shri G.K. Mishra, Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan) and Shri Sanjay Gupta authorized representative on behalf of PP. PP submitted that about 4.5% construction has been completed without obtaining EC and thus the case falls under the violation category. During presentation, it was observed by the committee

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

that PP has not submitted the specific and justifiable reply of all TOR point and needs detailed justification. Thus after presentation, PP was asked to submit response on following issues with revised details:

1. Detailed, specific and justifiable reply of all TOR point issued for carrying out EIA.
2. Justifiable details of 4.5% constructed area with supported evidences.
3. Commitment of PP that 30 meters shall be left from the HFL of nearby drain and this area will be developed as green belt.
4. Revised carbon foot print analysis as discussed during presentation.
5. Please provide 10KW grid solar panel backup calculation and with solar street lights.
6. Revised damage assessment and remediation plan as discussed during presentation.
7. Backup calculation of proposed population of 3645 peoples and if revision is proposed, please includes all activities such as banquet hall, Multiples etc. Similarly, if population is revised, please submit revised details of MSW, Water requirement and Waste Water Treatment Facility etc.
8. Clarification regarding G+ 1 detail proposed for flats in EIA.

PP has submitted the online query reply raised in 600th SEAC meeting dated 18-10-22 through “Parivesh Portal” on dated 22.10.2022 and thus the case was scheduled in this SEAC meeting. The query reply case was presented by the Env. Consultant Shri G.K. Mishra, Global Management and Engineering Consultants International, Jaipur, (Rajasthan) and Shri Sanjay Gupta authorized representative on behalf of PP, wherein PP submitted that they have submitted revised EIA report incorporating all revised details and other relevant documents and their details are as follows:

- We have checked and updated all TOR points briefly please refer Ch. 1 of Final EIA report.
- Regarding Justifiable details of 4.5% constructed area with supported evidences PP submitted 4.5% Construction has been done at the project site which contains the construction of Internal road, internal Boundary, 8-10 Plots, MOS of Multi Units, Boundary wall with main gate and plantation nearby Gate area and Site office building.
- Commitment of PP that 30 meters shall be left from the HFL of nearby drain and this area will be developed as green belt- We have already left out 30m of Landscaping land from HFL of nearby drain to multiunit building. Kindly refer chapter 2 of Revised Final EIA report.
- Revised carbon foot print analysis as discussed during presentation- There is 0.15 metric ton of Carbon Emission during an entire year over which we have proposed 600 trees those will absorb 5.940 metric tons of Carbon. Carbon Footprint calculation has been discussed in Ch. 2 of Revised Final EIA report.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

- Details regarding 10KW grid solar panel backup calculation and with solar street lights- 40 street lights of 4 kw have been installed & 6 kw solar panel will be installed on Roof of Multi units details have been discussed in Ch. 2 of Revised Final EIA report.
- Revised damage assessment and remediation plan as discussed during presentation- Revised remediation plan has been discussed in Chapter 13 of Revised Final EIA report.
- Backup calculation of proposed population of 3645 peoples and if revision is proposed, please includes all activities such as banquet hall, Multiples etc. Similarly, if population is revised, please submit revised details of MSW, Water requirement and Waste Water Treatment Facility etc.- Population has been revised and all details incorporated in Ch. 2 of Revised Final EIA report.
- Clarification regarding G+ 1 detail proposed for flats in EIA- Multi - Storey Building total floors are G+10 and Duplex building are G+1 and we have exclude the G+ 1 detail from revised final EIA report. PP submitted damage assessment and remediation plan as:

Damage Assessment Plan:

Project Description	Proposed estimated		Damage Assessment	Management plan
Soil	Total Land area – 47,170.00 sqm Total Excavated material - 80,054.226 cum (7 m max. depth) Top Soil – 11,436.318 cum (1 m depth) Excavated material – 68,617.908 cum (6 m Depth)		Till dated ground coverage area - 514.62 sqm Total excavated material – 3,602.34 cum (7 m max. depth) Top soil – 514.62 cum (1 m depth) Excavated material – 3,087.72 cum (6 m depth)	Total 514.62 cum top soil will be 100% utilized for plantation (Landscape area – 4658.50 sqm) Rest of material will be used for backfilling of entire project
Water harvesting	Pre <ul style="list-style-type: none"> • Total land area - 47,170.00 sqm • Recharge potential – 106.1325 cum/hr 	Post <ul style="list-style-type: none"> • Ground Coverage – 11,436.318 sqm • Recharge potential – 302.22 cum/hr 	Pre stage construction recharge potential was 106.1325 cum/hr Post stage recharge potential will be 302.22 cum/hr Now, systematic	For systematic recharge we have proposed 13 no. of RWH pits with capacity of 28.26 cum each it will be designed as per

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

			recharge potential will be increase upto 43.146 cum/hr Till date ground coverage of area 514.62 sqm has been covered accordingly drainage and pits has been implemented for the constructed area	the CGWA norms.
Water body	At present project area falls under the residential/commercial zone. No water body/natural drain is passing through the proposed project site		No water Body	All storm water drainage water system will be developed to maintain the natural recharge
Landscaping	Pre Total land area – 47,170.00 Sqm. Earlier some bushes and thorny plants at site .	Post At the time of implementation of the project all bushes and thorny plants has been cleared and in our project we were proposed 600 trees and Plants for landscaping development	For the clearance of the site we have cleared all the bushes and thorny plants accordingly for the better landscaping and aesthetic beauty of the project we are developing dedicated 4,658.50 sqm area and be additional peripheral plantation	Total 600 trees and Plants like Neem, mango, Ashok, Guava etc. will be planted on site .

Remediation Plan :

S. No	Environmental Factors/ Attributes	Remedial Plan/ Augmentation Plan	Remedial Cost		Environmental Management Plan	EMP Cost		Remarks
			Capital	Recurring		Capital	Recurring (Annual)	
1.	Land use as per Approved Master Plan by TNCP, Bhopal	Broken land is as per master plan approved by T&CP	-	-	Project Cost Capital Cost	OWN LAND	--	T & CP Letter No. BPLLP-

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

		(enclosed land use area breakup & Undertaking as Annexure – I & II) NO VIOLATION			Land cost		--	6914/एल.पी 140. /29(1)/नग्रानि/जि का 2020/भोपाल, दिनांक 19.08.2020
2	Environmental Sensitive Places, Land Acquisition Status, Resettlement & rehabilitation	Land is in possession of Companyenclosed land revenue record No R & R Applicable NO VIOLATION	-	-	Land is in possession of. All land records is enclosed with our EC Application.	-	-	
3	Baseline Environmental Quality (Aug 2021- March 22)	All the parameters are in the comfort zone in one season EIA study Monitoring data from Aug 2021- March 22 is pending @ 15000/ year * 1 Years (2 Air, 2 Noise, 1 water)	--	15,000 (amount may be proposed for additional plantation or as per the suggestions of SEAC/ SEIAA)	-	-	5,000	We have done EIA study. All baseline data results are found satisfactory
4	A) Land	Total land area 47,170.00 sq.mt. & Built Up Area – 98,714.54 sq.mt. Topsoil = 514.634 Cu.m. (1 m depth) (4.5 % of total ground coverage has been excavated till now as 4.5 % of construction has been done. Total quantity of topsoil has been used for Mulching & Podium	-	-	Land is in possession of Signature Builders & Colonizers under joint registered joint venture. All land records are enclosed with our EC Application.	-	-	No Violation

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

		Development 30% of excavated soil used for Land Fill • And Rest of Excavated Soil Used for Lawn Development, & landscaping area.						
	B) Ground Water	No new ground bore well is done for construction purpose.	--	--	Not applicable, till date no bore well for ground water tapping is proposed.	--	--	NO VIOLA TION
	C) Surface water	Not applicable, No Water body exist within the project lease area	--	--	Not applicable	--	--	NO VIOLA TION
	D) Air	Water sprinkling had been done as per terms & condition of the work order agreements (2 water tankers/ day)	--	--	Constructio n period = 8 months , Working Day = 240 day Per day water requirement = 10 KLD (2 Tanker @ 100/ tanker water cost)	--	48,000	In House Arrange ment
	E) Biodiversity	NOT APPLICABL E	--	--	NOT APPLICAB LE	---	--	We have not created any change in the biodiver sity of the area.
	f) Noise & Vibration	Site is fully barricaded NOT APPLICABL E			All new machinery has been used on site. Construction work proposed	--		

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

					only for day time therefor there is no noise disturbance at night.			
	g) Socio economy & Health	-	-	-	-	-		Done in EIA study
	g.a. Occupational Health check-up for 35 Workers	Initial Medical Examination (IME) for 35 workers Deployed on site (35 X 1000 X 5)	--	1,75,000 (amount may be proposed for additional plantation or as per the suggestions of SEAC/SEIAA)	Initial Medical Examination (IME) for 35 workers deployed on Site. (1000 Rs/workers) for a year.	-	25,000	Total Calculated value for occupational health and check-up, PPE's and Worker's
	g.b. Personal Protection Equipment's	All PPE's distrusting to the labourer and staffs are under contractor's scope. 35X1200)		42,000 (amount may be proposed for additional plantation or as per the suggestions of SEAC/SEIAA)	Helmet, Jackets, hand gloves & Boots will be Provide to 35 Workers for remaining 40% construction work.	30,000	5,000	Shelter have been covered under remedial cost
	g.c. Shelter and Sanitation for 35 workers	Temporary shelter & Mobile toilet has been provided to the workers	--	--	Provision of Temporary shelter & Mobile toilet will be extended in numbers during the time of construction for 35 workers	20,000	-	
5	Contour Plan With slopes, Drainages pattern of the site and	No conversion is done in storm water drainage pattern on site	-	-	--	-	-	No Violation

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

	surrounding area any obstruction of the same by the projects.							
6	Tree Felling	--	-	-	No tree felling is proposed.			No tree felling is proposed.
7	Tree plantation	Total 600 trees planted & development of landscaping area (600 trees @Rs. 500+landscaping development)	-	-	All type of landscaping development & maintenance including tree cost	10,00,000	1,90,000	All remedial cost will be utilized for left over plantation & further development of additional landscaping.
8	Permission for forest Land	NOT APPLICABLE	-	-	NOT APPLICABLE	-	-	No forest area is involved in this project.
9	Environment policy	Policy is part of Terms & Condition of mutual Agreement	-	-	-	-	-	Policy is part of Terms & Condition of mutual Agreement.
10	Ground Water Classification	At construction phase no ground water has been used.	-	-	At construction phase no ground water has been used,	--	--	No violation
11	Source of Water	A – Construction Phase	--	--	--	--	--	During Construction phase we have used

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

								Water Tanker of Rs. 1, 65,000/- .
		B – Operational Phase	--	--	--	--	--	Water supply permission vide Provisional Bulk Connection letter no. QT/सं.यं./ज.का./जोनक्र. 16/2020 Bhopal, Dated 18/11/2020.
12	Source of Waste Water Treatment	500 KLD STP installed.	--	--	500 KLD STP (installed) – Rs. 10, 00,000 for civil construction (Labour &Material Cost) 6, 00,000.00 for mechanical installations .	40,00,000	4,00,000	
13	Dual Plumbing	Dual Plumbing for 4.5% of constructed area has been completed.	--	--	Dual Plumbing for 4.5% of constructed area has been completed.	3,50,000		
12	Rain Water Harvesting	13 No. Rain water harvesting pit has been constructed for the project.	--	--	Total 2 nos. of pits are proposed on site for operational phase	3,90,000	90,000	--
13	Soil Characteristics	Total land area 47,170.00	--	--	8m depth of rain water	--	As per above	NO VIOLA

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

	& Ground Water Table Top Soil Conservation	sq.mt. & Built Up Area – 98,714.54 sq.mt. Topsoil = 514.634 Cu.m. (1 m depth) (4.5 % of total ground coverage has been excavated till now as 4.5 % of construction has been done. • Total quantity of topsoil has been used for Mulching & Podium Development • 30% of excavated soil used for Land Fill • And Rest of Excavated Soil Used for Lawn Development , & landscaping area.			harvesting pits have been proposed, Quality of top soil & costing of its disposal			TION
14	Solid Waste Generation Treatment	All the construction waste has been reused for the filling of the low-lying project area.	50,000	--	Solid Waste will be reused in proposed boundary wall & stone pitching to reduce RCC work on site	00	00	MSW NOC is attached with hard copy reply. Vide letter no. 196/स्वा. विभाग / 2022 Bhopal dated 28/01/2022
		Permission for Disposal of Solid waste from BMC obtained from 2014	--	--	Street garbage shall be controlled segregated transferred and disposed-off by Nagar Nigam Bhopal	--	50,000	
15	Energy	Solar light	5,00,000	--	Provisional	--	30,000	We

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

	conservation & Energy Efficiency (LED bulb & Solar System)	proposed 10 KW			of the solar panels for streets lighting & common areas and LED light for commercial unit			have proposed Solar Power of 10 KW.
16	D G Sets	Till date RMC has been used for construction.	-	-	-	--	--	We have not used DG set in our construction phase.
17	Parking & Roads	Approach road already exists sufficient space excises for Parking	-	-	Development of Open Parking & Other Services -	20,00,000	--	All adequate parking facilities have been provided as per T&CP norms.
18	Transportation of materials for construction	Till date on 4.5% construction have been done.	--	1,00,000 (amount may be proposed for additional plantation or as per the suggestions of SEAC/SEIAA)	Storage hall/service yard will be for materials stacking during further 86.82 % construction .	--	--	Some miscellaneous transportation work had not been done in appropriate manner. We are proposing some rounded amount in our remediation cost.
19	Disaster Management	-	-	-	Centralized control room	--	--	--

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

	Plan				with ERP system			
	a) Fire	Machines were equipped with their fire extinguishing equipment. Till date on 4.5% construction have been done	3,35,000 (amount may be proposed for fire machinery installation)		Fire fighting organizing and arrangement: External fire hydrant system, hose pipes, pumps with control panel, overhead tanks, first aid, fire extinguishers, sand buckets, Manual and automatic fire alarm, main security room etc.	50,00,000	2,00,000	All fire & safety facilities have been provided for the 4.5% constructed area.
	b) Accidental & First aid etc.	First aid kit & room provided on site, enclosed photos No accident or injury is reported during the earlier construction period.	50,000	5,000	First aid kit for worker's safety on site			
	c) Safety	All loading machines, dumpers & Equipment will be deployed as per safety norms mentioned in Agreement.	1,00,000	-	All loading machines, dumpers & Equipment will be deployed as per safety norms mentioned in Agreement.			
Total			10,35,000/-	3,37,000	-	1,27,90,000	10,43,000	-
Total Capital cost for Remedial Plan			Say in Lacs	10.35	Total capital cost for EMP	Say in Lacs	127.900	
Total recurring cost for Remedial Plan			Say in Lacs	3.67	Total Recurring Cost for EMP	Say in Lacs	10.43	

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

Committee evaluated the reply and found satisfactory and acceptable and recommends that PP shall deposit the bank guarantee with three years validity of Rs. 14.02 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.

Further, this being a violation case for which Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) dated 15/07/2021 as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India to deal with the violation cases. Penalty provisions as per para 12 (i) of the notification will be applicable i.e. 1% of the total project cost incurred upto date. PP has submitted that cost incurred till date is 08.68 Crores (land cost 05.58 Cr as per the cost mentioned in the registry of year 2011-12 and construction cost till date is 03.10 Cr). As the operation has not started the penalty provision works out to be Rs. 08.68 lakh . PP further submitted that as per clause 12.2 of OM dated 07/07/21 the percentage rates shall be halved since they have suo-moto reported this violation and thus penalty of Rs. 04.34 lakhs shall be levied on them. Committee discussed on this issue and recommends that the provision claimed by PP as per the OM dated 07/07/21 may be considered subject to the approval of SEIAA.

The EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Environment Clearance for Construction of Sage Golden Spring Residential Apartment at Village - Damkheda, Patwari, Halka No. 21, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP). [Total Plot Area – 47170.00 Sq.mtr. (4.717 ha.), Built Up Area - 98714.54 square meter], subject to deposit bank guarantee of Rs. 14.02 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan including capital & recurring cost) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA, Penalty @ 1% or @ 0.5% of the total project cost incurred upto the date of filling of application i.e Rs. 08.68 lakh or Rs. 04.34 lakhs as per clause 12 a.i. of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 as decided by SEIAA and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act,1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 with following conditions:

I. Statutory compliance:

- i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project (if any).
- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

- Wildlife (if applicable).
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee
 - iv. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) of CWC (if applicable).
 - v. Necessary approval of CEA shall be obtained for those projects having the project cost more than Rs. 1,000 crore (if applicable).

II. Air quality monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released covering upwind and downwind directions during the construction period.
- iv. 04 nos. of Diesel power generating sets of 2100 kVA (600 KVA + 500*3 kVA) are proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- v. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- vi. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

- vii. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- xi. The gaseous emission from 04 nos. of DG set (2100 kVA) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement and waste water generation during construction phase are as follows :

S.No.	particulars	Water Requirement (KLD)	Wastewater Generation (KLD)	
			Quantity (KLD)	Remarks
1.	Domestic Water for Workers (35@45lpcd)	1.575 KLD	1.33 KLD	85% Wastewater will be deposited into septic tanks
2.	Dust Suppression	3 KLD	2.4 KLD	Losses 20% loss on washing: rest will be collected and reused for curing after necessary treatment

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

3.	Washing of construction Equipment	4 KLD	4 KLD	-
4.	Curing	4KLD	4 KLD	Losses
Total		12.575 KLD	11.73 KLD	-

iv. The total water requirement during operation phase are as follows

S. No.	Item Description	Number of Persons I Seats / Area	Water Requirement/ head(liters)	Total water Requirement (liters)
A	Fresh Water Requirement			
1.	Residential (Flats + LIG + EWS + Plots + Shops + offices + Restaurent + Gaming zone + Food Court Shops)	(2,950 + 132 + 195 + 258 + 306 + 77 + 10 + 2 + 17) = 3947	90	3,55,230
2.	Staff	336	20	6,720
3.	Visitors	1,000	5	5,000
	Subtotal of A			3,66,950
B	Flush Water requirement			
1.	Residential (Flats + LIG + EWS + Plots + Shops + offices + Restaurent + Gaming zone + Food Court Shops)	(2,950 + 132 + 195 + 258 + 306 + 77 + 10 + 2 + 17) = 3947	45	1,77,615
2.	Staff	336	10	3,360
3.	Visitors	1,000	10	10,000
	Subtotal of B			1,90,975
C	Other Uses			
1	Landscaping	4658.50 Sq.m.	5	23,293
	Total Water Requirement			5,81,218
				581.218 KLD

v. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be to monitor to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

- vi. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vii. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- viii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- ix. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- x. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- xi. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xii. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xiii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiv. For rainwater harvesting, 13 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about $28.26 \text{ m}^3/\text{hr}$. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. Total wastewater generated in construction Phase is 11.73 KLD & wastewater generated in operation phase will be 485 KLD which will be treated in the STP of 500 KLD (MBBR based technology). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing. AC makes up water and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in MBBR based STP of 500 KLD capacity and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time .

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

V. Energy Conservation measures.

- i. 10 KW on grid Solar Plant will be installed. This will be used to give electricity backup to Solar Street light. In addition to this 50 nos. of charging point will be provided in stilt parking to increase in the use of the Electrical vehicle.
- ii. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- iii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iv. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

VI. Waste Management

- i. Total waste generation is 2207 kg/day as per following category and these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules 2016.

S. No.	Category	Kg per capita per day	Waste generated (kg/day)
1	Residential	3947 @ 0.5 kg /day	1973.5
2	Staff	336 @ 0.25 kg / day	84
3	Visitors	1,000 @ 0.15 kg / day	150
4	Landscape waste (4658.50 m ²)	1.15114042 @ 0.2 kg/acres	0.23022
Total Solid Waste Generated			2207.730 kg/day Say 2208 kg/day

- ii. Manage the site in accordance with Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 and amended Rules, 2016 and the electronic waste is managed as per the guidance of E-waste (Management and Handling) Rules 2016.
- iii. Any additional muck generated from remaining activities, will be disposed off at nearby villages with due consent of local administration/gram

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

panchayat. As the pipeline passes along the villages, villages will fall within 1-5 Km along the route of pipeline.

- iv. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VII. Green Cover

- i. Total 600 trees planted & development of landscaping area in the 4658.50 Sq.M.with following break-up:

Peripheral plantation	75 big trees and 150 ornamental trees
Roadside plantation	225 ornamental trees
Nearby entry exit plantation	50
Along with Garden area	100 Ornamental trees

- ii. Not tree shall be felled / uprooted.
- iii. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.
- iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.
 - c. Proper design of entry and exit points.
 - d. Parking norms as per local regulation.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

- ii. Total proposed Parking's arrangement for 1156ECS with following arrangement:
- Multiplex/ Shopping Mall – 201 ECS
 - Flats – 576 ECS
 - Plots – 129 ECS
 - Additional Parking – 250 ECS
 - Total parking proposed = 1,156 ECS
- iii. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.
- vii. Rest Room, Drinking Water and Toilets Facilities shall be provided for floating servants/workers in the common areas of the project.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

X. EMP & CER

- i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. PP has proposed 138.33 Lakh (including capital Rs. 127.90 Lakh and 10.43 Lakhs as recurring cost) for this project and PP, M/s Vrindavan Construction, Partner, Shri Arun Agrawal S/o Late Shri R.P.Agrawal, 250, Sagar Plaza, Zone-II, M.P. Nagar, Dist. Bhopal, MP has proposed to submit a guarantee with three years validity of Rs. 14.02 lakh towards Remediation Plan. In addition, expenditure already incurred on implementation of EMP is Rs. 3.50 Lacs.
- vi. For this project PP has proposed Rs 05.00 Lakh as Corporate Environment Responsibility (CER):

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

CER activities as per notification	Proposed Budget for CER
Van Vihar National Park – Eco Development and Staff Welfare which shall be carriedout in the first year of commencement of the project.	5 lakhs

XI. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
- iii. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

14. Case No 6769/2020 M/s R.K.Stone Company, Partner Shri Aasif Khan, Ward No. 08, Khudwari Mohalla, Barod Road, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5,044 cum per annum) (Khasra No. 385/2/2), Village - Jeevangarh, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam (MP). EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 385/2/2), Village - Jeevangarh, Tehsil - Alote,

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

Dist. Ratlam (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 422वीं दिनांक 10/02/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

सेक की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन-लाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र पश्चिम दिशा में 90 मीटर दूरी पर पक्का रोड़ निकल रहा है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह ग्रामीण पक्का मार्ग है। इसी प्रकार खदान के दक्षिण दिशा में लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक डेम है जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि हमारे द्वारा गारलेंन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किया गया है तथा सेटलड वाटर का निस्तारण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान मिनरल इवेक्वेशन रोड़ पर जल छिड़काव, वृक्षारोपण व सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण के कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. एवं सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. एवं वृक्षारोपण योजना।
- ✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 16/06/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो संतोषजनक पाई गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन— 5,044 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.76 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.37 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख :-

क्रं.	जन सुनवाई आधारित सीईआर गतिविधियां	राशि रु. में
01	जीवनगढ़ गांव तहसील अलोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पोर्टेबल ईसीजी मशीन का वितरण।	40,000/-
02	जीवनगढ़ गांव के प्राथमिक विद्यालय के समस्त छात्रों को टिफिन, जूते, स्कूल	20,000/-

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

	बैग का वितरण ।	
	योग	60,000 /—

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा रख-रखाव दूसरे वर्ष से लीज अवधि तक किया जावेगा

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	आंवला , कस्टार, जंगल जलेबी, चिरोल, अचार ,आदि स्थानीय प्रजातियाँ ।	250
2	परिवहन मार्ग	शीशम, अमलतास, जामुन, चिरोल, करंज, स्थानीय प्रजातियाँ	110
3	जीवनगढ़ व गुलबलोद, भवगढ़ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	अमला, बेल, नीबू, आम, सिशु, जामुन, शीशम, इमली, महुआ, अन्य फलदार प्रजातियाँ ।	820
4	जीवनगढ़ गांव के विद्यालय में	अशोक, नीम, अमलतास, गुलमोहर ।	20
कुल			1200

प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिया में दिनांक 22/09/22 को ई-मेल के माध्यम आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया कि माननीय एन.जी.टी. के मापदण्ड को मानते हुए खनन कार्य रॉकब्रेकर द्वारा किया जावेगा और ब्लास्टिंग नहीं की जायेगी।

सिया की 750वीं बैठक दिनांक 13/10/22 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत नॉन ब्लास्टिंग के आवेदन अनुसार प्रकरण को पुनः परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु सेक प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण को सेक की आज बैठक दिनांक 04/11/22 को समिति क समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑनलाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोएडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग का प्रस्ताव दिया गया था किंतु खदान क्षेत्र पश्चिम दिशा में 90 मीटर दूरी पर पक्का रोड़ होने के कारण तथा स्टोन का उत्पादन बहुत कम (5044 घनमीटर/वर्ष) होने के कारण वे अब ब्लास्टिंग के स्थान पर खनन कार्य रॉकब्रेकर के माध्यम से करेंगे । समिति ने चर्चा में पाया कि खदान के पश्चिम दिशा में 90 मीटर दूरी पर पक्का ग्रामीण रोड़ निकल रहा है जो म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के अनुसार प्रतिबंधित दूरी 50 मीटर से अधिक दूरी पर है तथा अनुमोदित खनन योजना में ब्लास्टिंग अनुमोदित है । अतः यदि परियोजना प्रस्तावक ब्लास्टिंग के स्थान पर खनन कार्य रॉकब्रेकर के माध्यम से खनन करना चाहे तो समिति को कोई आपत्ति नहीं है तथा अन्य शर्तें समिति की 578वीं बैठक दिनांक 16/06/22 की गई अनुशंसानुसार यथावत रहेगी ।

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

15. Case No 9386/2022 M/s Sharma Associates, Partner Shri Dinesh Sen, Devri Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487330, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.0 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Chhituraha, Tehsil - Patan, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Chhituraha, Tehsil - Patan, Dist. Jabalpur (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1595 दिनांक 24/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐरिया मैप के अनुसार वन क्षेत्र लगभग 110 से 120 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1595 दिनांक 24/05/2022) अनुसार 250 मीटर के अंदर कोई वन क्षेत्र नहीं है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशांसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडिड गूगल इमेज अनुसार आवटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग 110 से 120 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः परियोजना प्रस्तावक संभागीय आयुक्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्रस्तुत करे तथा प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये।

16. Case No 9387/2022 M/s Sharma Associates, Partner, Shri Dinesh Sen Devri Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487330 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.0 ha. (15,800 Cum per annum) (Khasra No. 01, 42), Village - Mahuakheda, Tehsil - Patan, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01, 42), Village - Mahuakheda, Tehsil - Patan, Dist. Jabalpur (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

प्रमाण-पत्र क्रमांक 1593 दिनांक 24/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान हिरन नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 1583 दिनांक 09/09/22 द्वारा अनुमोदित जबलपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है जिसके पेज नं. -61 के सरल क्रमांक-34 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-24,000 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 24,000 घनमीटर है, तथा कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 23/09/22 अनुसार खदानवार मात्रा अनुसार इस खदान की उत्पादन क्षमता 15,800 घनमीटर उल्लेखित है अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 15,800 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग नदी के जल में डूबा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही माइनिंग की जायेगी तथा खनन क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन हेतु उपलब्ध क्षेत्र लगभग 01 हे. तथा गहराई 02 मीटर स्वीकृत है जिसके अनुसार 15,800 घनमीटर रेत निकाली जा सकती है। रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी भाग से किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष ही हेतु ही है तथा समिति का यह चिंता है कि 01 वर्ष पश्चात् रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत - 15,800 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 19.57 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.63 लाख प्रति वर्ष।
3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 07.20 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे ।
5. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटग बॉसं जामुन, कहवा, खस, नागर मोथा, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1200
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	आमा, हल्दी, लक्ष्मण कन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, वायविडन, कालमेघ अन्य प्रजातियां वन विभाग के सुझाव अनुसार	800
2	ग्राम छितुरहा के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	400
कुल			2400

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
तहसील- पाटन के शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में पाँच ब्हीलचेयर	60,000 / -
योग	60,000 / -

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

17. Case No 9388/2022 M/s Sharma Associates, Partner, Shri Dinesh Sen, Devri Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487330 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (60000 Cum per annum) (Khasra No. 464), Village - Saliwada, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 464), Village - Saliwada, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1598 दिनांक 24/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 1583 दिनांक 09/09/22 द्वारा अनुमोदित जबलपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है जिसके पेज नं. -57 के सरल क्रमांक-02 पर माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-72,000 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 72,000 घनमीटर है, तथा कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 23/09/22 अनुसार खदानवार मात्रा अनुसार इस खदान की उत्पादन क्षमता 60,000 घनमीटर उल्लेखित है अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 60,000 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान का कुछ भाग नदी के जल में डूबा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित क्षेत्र का वह भाग जो नदी में डूबा है वहाँ से खनन कार्य नहीं किया जायेगा। रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा नर्मदा नदी में होने के कारण खनन कार्य मैन्युली किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष ही हेतु ही है तथा समिति का यह चिंता है कि 01 वर्ष पश्चात् रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 60,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. खनन कार्य नर्मदा नदी होने के कारण मेन्युली किया जाये।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 25.75 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 03.88 लाख प्रति वर्ष।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 12.90 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
6. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटग बॉस, जामुन, कहवा, खस, नागर मोथा, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2200
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	आमा, हल्दी, लक्ष्मण कन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, वायविडन, कालमेघ अन्य प्रजातियां वन विभाग के सुझाव अनुसार	2200
3	ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	400
कुल			4800

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय चिकित्सा केंद्र बरघी में तीन स्टील की बेंच और पॉच बेड गददे बेड के साथ	100000 / -
योग	100000 / -

18. Case No 9389/2022 M/s Sharma Associates, Partner, Shri Dinesh Sen, Devri Rajmarg, Dist. Narsinghpur, MP - 487330 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.023 ha. (36414 Cum per annum) (Khasra No. 1/1), Village - Sagda Jhapni, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1), Village - Sagda Jhapni, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) 2.023 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश सेन (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1596 दिनांक 24/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया के पत्र क्रमांक 1583 दिनांक 09/09/22 द्वारा अनुमोदित जबलपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की है, जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज है जिसके पेज नं. -57 के सरल क्रमांक-01 पर माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत)-36,414 घनमीटर उल्लेखित है। चर्चा के दौरान समिति ने निर्धारित किया गया कि चूंकि अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 60 प्रतिशत माइनेवल मिनरल पोर्टेंशियल 36,414 घनमीटर है, तथा कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्रमांक 2647 दिनांक 23/09/22 अनुसार खदानवार मात्रा अनुसार इस खदान की उत्पादन क्षमता 36,414 घनमीटर उल्लेखित है अतः पर्यावरणीय अभिस्वीकृति इसी मात्रा अर्थात् 36,414 घनमीटर हेतु अनुशंसित किया जाये। रेत का परिवहन आवंटित खनन क्षेत्र के दक्षिण-पूर्वी भाग से किया जायेगा तथा नर्मदा नदी में होने के कारण खनन कार्य मेन्युली किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष ही हेतु ही है तथा समिति का यह चिंता है कि 01 वर्ष पश्चात् रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा। अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल भी करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता रेत – 36,414 मी³ प्रति वर्ष।
2. खनन कार्य नर्मदा नदी होने के कारण मेन्युली किया जाये।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैंपीटल राशि रु. 20.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 02.80 लाख प्रति वर्ष।
4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगे कि खनन क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 07.45 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे।
6. वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक स्वयं निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य (सतत सिंचाई, 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कटंग बॉस, जामुन, कहवा, खस, नागर मोथा खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1250
2	आवंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (कैंचमेंट एरिया-इच्छुक ग्रामीणों के खेत) में	आमा, हल्दी, लक्ष्मण कन्ध, अश्वगंधा, ब्राह्मी, केवकंध, वायविडन, कालमेघ अन्य प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	800
3	ग्राम छितुरहा के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाड़ी, शासकीय	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य	400

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 नवम्बर 2022

	विद्यालय में	स्थानीय प्रजातियाँ।	
			कुल 2450

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
स्थानीय ग्रामीणों के लिए बीपी व शुगर पेशेंट के लिए मेडिकल कैंप लगायेंगे।	40,000 /—
प्राथमिक विद्यालय, सगड़ा झपनी के सामाजिक कल्याण के लिए योगदान (छात्रों के लिए खेल किट और स्टील की दो बेंच दिया जायेगे।)	40,000 /—
योग	80,000 /—

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 04 नवम्बर 2022

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

- i. Minal Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 04 नवम्बर 2022

15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 04 नवम्बर 2022

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

603वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 04 नवम्बर 2022

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

- नोट 7 :-** बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained